

श्रम संसाधन मंत्री के तौर पर किये गये बड़े बदलाव एवं कार्य

श्री विजय कुमार सिन्हा जी जब श्रम संसाधन विभाग के मंत्री पद का कार्यभार संभाला तब इस विभाग के बारे में बिहार की आम जनता को कुछ खास जानकारी नहीं थी और इन्होंने श्रम संसाधन विभाग का बिहार में चल रहे कार्यकलापों का अवलोकन कर दूरदर्शी सोच से सर्वप्रथम अपने छः सुत्री मिशन को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया। जिससे इस विभाग की जानकारी जन-जन तक पहुँच सके और इससे बिहार की जनता लाभान्वित हो सके। इनका पहला संकल्प श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए था, दूसरा प्रशिक्षण पक्ष में रचनात्मक बदलाव करने एवं पारदर्शी बनाने के लिए संकल्पित हुए, तीसरा नियोजन पक्ष के माध्यम से नौजवानों को नये रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संकल्पित हुए, चौथा कौशल विकास के माध्यम से डिजिटल इंडिया का योद्धा बनाने के लिए संकल्पित हुए, पाँचवा श्रमिकों एवं उनके परिवार को स्वस्थ रखने के लिए संकल्पित हुए और छठा संकल्प समाज के अभिशाप बालश्रमिकों के उन्मूलन तथा प्रवासी श्रमिकों के दोहन-शोषण से मुक्ति दिलाने का था। इन सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम इन्होंने एक नीति के तहत अभियान के तौर पर पूरे बिहार के सभी जिलों का दौरा किया और प्रत्येक जिले में अपने उक्त संकल्पों को पूरा करने का अभियान चलाया।

प्रत्येक जिला में दौरा कर कामगार श्रमिकों का निबंधन करवाया, श्रम विभाग के पदाधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के मौजूदगी में बैठक कर श्रम विभाग की योजनाओं को वास्तविक श्रमिक तक पहुँचाने और उनको श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाये जा रहे सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का लक्ष्य दिया, वास्तविक श्रमिकों के निबंधन को सरल एवं सुलभ करने के लिए बिचौलियागिरी को खत्म करने का निदेश दिया, पुराने सभी निबंधन को पारदर्शिता के साथ आधार कार्ड से जोड़कर नवीनीकरण करते हुए गलत नामों का संशोधन करने का निदेश दिया जिससे नये वास्तविक श्रमिकों को उनका शपथ पत्र लेकर ऑनलाईन निबंधन करने का निदेश दिया साथ ही इन्होंने यह भी निदेश दिया कि यदि गलत लोगों का निबंधन किया जायेगा तो संबन्धित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और श्रमाधीक्षक की जिम्मेदारी तय की जायेगी। दौरा के क्रम में ही एन0डी0ए0 के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं से अवगत कराया ताकि एक सामाजिक सिपाही बनकर वो लोग भी विश्वकर्मा के संतान श्रमिकों को इसका लाभ पहुँचाने में मददगार बनें, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत चल रहे कुशल युवा प्रोग्राम का मॉनेटरिंग कियें जिससे जो भी खामियाँ थीं वह इनके समक्ष आई जिसको लेकर इन्होंने कई रचनात्मक बदलाव कियें, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण कर वहाँ की स्थिति को जाना और जो भी समस्या आया उसको दूर करने का प्रयास किया।

जब पूरे बिहार के प्रत्येक जिले में अपने अभियान के तहत दौरा किया तब इस विभाग की वास्तविक खामियाँ सामने आयी और तब इन्होंने सर्वप्रथम मजदूर को मजबूर, लाचार और बेबश की परिभाषा से मुक्त कराने का सफल प्रयास प्रारम्भ किया और इन्होंने इनका उचित परिभाषा देते हुए कहा कि मजदूर, मजबूर नहीं सृजनकर्ता, निर्माता, विश्वकर्मा की संतान है और इनका सम्मान राष्ट्र का उत्थान है। विजय कुमार सिन्हा जी श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से गरीब एवं श्रमिकों के कल्याण एवं उत्थान हेतु, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ प्रयासरत हुए और मजदूर को मजबूर की परिभाषा से हटाकर श्रमिक, सृजनकर्ता, निर्माता, विश्वकर्मा की संतान के रूप में जनजागृति का प्रारंभ किया। श्रम विभाग के अंदर लोगों की मानसिक सोच में बदलाव करते हुए **श्रमिक का सम्मान राष्ट्र का उत्थान** के लिए जन्म से मृत्यु तक की लगभग एक दर्जन से ज्यादा योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए सघन अभियान चलाया। जब ये मंत्री बने थे तब 7.5 लाख के लगभग भवन कामगार मजदूर निबंधित थे और नवीनीकरण करने तथा नये श्रमिकों का निबंधन करने के बाद आज 18 लाख श्रमिक निबंधित है। इन्होंने दो नई योजनाओं का प्रारम्भ किया पहला प्रत्येक मजदूर को वार्षिक चिकित्सा सहायता राशि के तहत तीन हजार (3000/-)

रूपये तथा प्रत्येक मजदूर को वस्त्र के लिए वार्षिक वस्त्र सहायता राशि के तहत पचीस सौ (2500/-) रूपये देने का निर्णय लिए। ये सहायता राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जायेगा, इस अनुदान में किसी भी तरह के धांधली को रोकने का सफल प्रयास किया। गरीब श्रमिकों के उत्थान के साथ सम्मान के लिए सेवा भाव से श्रमिक राज्य के विकास के संकल्प को बढ़ाने का कार्य किया। दोनों योजनाओं की घोषणा के बाद विभाग के अंदर कुछ लोग संशकित थे कि इतनी राशि कहाँ से आयेगी। इन्होंने श्रमिकों के लिए एक प्रतिशत शेष टैक्स की राशि को पारदर्शी बना दिया जिससे योजनाओं की राशि खर्च करने के पश्चात भी जो पूर्व की जमा राशि थी उसमें भी वृद्धि हुई। अनुदान खर्च की राशि लगभग नौ गुणा बढ़ा यह विभाग की बड़ी उपलब्धि थी।

श्रमिकों को स्वस्थ रखने के लिए भारत सरकार के साथ बैठक कर सभी जिले में ई0एस0आई0सी0 अस्पताल खोलने की घोषणा भारत सरकार से स्वीकृति दिलवाया और बिहार के श्रमिकों के लिए बिहटा, पटना में 500 बेड का बड़ा अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन माननीय केन्द्रिय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष गंगवार जी के कर कमलों द्वारा बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी की उपस्थिति में हुआ जिसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिहार के सभी जिलों में श्रम एवं नियोजन कार्यालय के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया (कुछ जगह प्रक्रियाधीन है)। समुद्र पार(विदेश जाने वाले) श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का भी प्रारम्भ किया गया है वाकि उनको वहाँ किसी भी तरह का दोहन-शोषण और प्रशासनिक परेशानी से बच सके और आवश्यकता पड़ने पर अप्रवासी/प्रवासी श्रमिकों को विभाग से सहायता मिल सके।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में बच्चों को सही ढंग से प्रशिक्षित कर कदाचार मुक्त परीक्षा लेने के लिए कटिबद्ध हुए जिसमें कई तरह की अड़चने आई किन्तु विजय कुमार सिन्हा जी अपने मार्ग पर अडिग रहें साथ ही साथ इंटरस्तरीय मान्यता दिलवाया जो एक ऐतिहासिक कदम था। बच्चें आगे की पढ़ाई जारी रख सके गरीब, श्रमिक, किसान और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चें का भविष्य बाधित न हो वो आगे की पढ़ाई की डिग्री ले सके और अलग से दो वर्ष इंटर करने की परेशानी से बच सके। गरीब के बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ-साथ सभी वर्ग के बच्चों को जूता तथा वस्त्र सरकार की ओर से वितरित करवाने का कार्य प्रारम्भ करवाया जिससे सभी बच्चें एक भाव से प्राप्त कर सके। यह पहल श्रमिकों एवं मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के हित में सराहनीय कदम था। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में एक रचनात्मक बदलाव करते हुए स्मार्ट क्लास चलाकर डिजिटल कंटेंट के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारम्भ करवाया।

सभी अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कार्य प्रारम्भ किया और आज लगभग सभी अनुमंडल और जिला में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अपने भवन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहें हैं। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कई खामिया संज्ञान में आया जो कि बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर कई राज्यों में भी खामिया समान थीं, जैसे नामांकन में गड़बड़ी, कम यूनिट से ज्यादा यूनिट बढ़ाकर नामांकन लेना बिना प्रशिक्षण के परीक्षा में बैठाना और सर्टिफिकेट देने की गारंटी देकर गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों से मनमानी वसूली के मामलों को लेकर भारत सरकार के कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के मंत्रालय के माननीय मंत्री के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर संज्ञान में लाए जिससे सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। बिना प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट वितरण की प्रक्रिया का समापन निकट भविष्य में सुनिश्चित है। गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण और पारदर्शी कदाचार मुक्त परीक्षा का वातावरण का निर्माण हुआ।

श्रमिकों, किसानों और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला में एक दिवसीय रोजगार मेला को दो दिवसीय किया और प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेला को त्रिदिवसीय किया। इसमें राज्य और राज्य के बाहर के कम्पनियों को आमंत्रित

कर नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास किया। प्रत्येक जिले के अनमंडल/प्रखंड स्तर पर नियोजन कैंप लगवाकर भिन्न-भिन्न कम्पनियों में रोजगार के साथ-साथ कम्पनियों द्वारा मार्गदर्शन देकर केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना एवं कई लाभकारी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करवाया जिससे बिहार के नौजवान रोजगार पाने के साथ नये रोजगार का सृजन भी कर सके।

श्रमिक और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को डिजीटल इंडिया में भागीदार बनने के लिए कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से अपने विभाग में निःशुल्क कम्प्यूटर ज्ञान, कौशल संवाद एवं कौशल व्यवहार का प्रशिक्षण में रचनात्मक परिवर्तन करते हुए पारदर्शी एवं सुगम और सुलभ बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर कौशल विकास केन्द्र खोला गया। नौजवानों को रोजगारोन्मुखी करने हेतु उनको कम समय में कौशल विकास के माध्यम से हुनरमंद बनाने के लिए कौशल विकास केन्द्रों के सिलेबस में कई बदलाव एवं सुधार करने और नये कोर्स जोड़ने का निर्णय लिए।

श्रम विभाग के अन्दर 10 लाख से ज्यादा दुकान, प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, कान्ट्रैक्टर शैक्षणिक और नर्सिंग संस्था में कार्य कर रहे श्रमिक निबंधित है। सभी व्यवसायिक संस्था में अकाउंट कार्य करने के लिए टैली, जी0एस0टी0 जानने वाले लाखों नौजवानों को रोजगार का अवसर है। इन्होंने विभाग के माध्यम से टैली, जी0एस0टी0 का कोर्स शुरू करवाया है जो आने वाले दिनों में इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। कई नये ट्रेड में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देकर रोजगार में भागीदारी का अवसर देने का अभियान शुरू किया है। आज लाखों बच्चें इसके लाभार्थी है और डिजीटल इंडिया का योद्धा बनकर बिहार एवं देश के विकास में अपना रचनात्मक योगदान दे रहें हैं।

बाल श्रमिक मुक्त बिहार बनाने के लिए इन्होंने दो भाग में अभियान चलाया एक व्यवसायिक क्षेत्र में बाल श्रमिक मुक्त करना और दूसरा घरेलू क्षेत्र में इसके लिए दुकान प्रतिष्ठान एवं फैक्ट्री में शपथ पत्र लेकर व्हाट्सएप्प मोबाइल नंबर जारी कर जनजागृति अभियान शुरू किया। आज दो दर्जन से ज्यादा शहर और जिलों में बाल श्रमिक मुक्त बिहार बना। इनको जेनेवा में किये गये संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक ऑर्गनाइजेशन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। बालश्रमिक विद्यालय शुरू करवाया ताकि उन्मुलित बच्चे दुबारा बालश्रम की ओर न जा सके। बालश्रम उन्मुलन के लिए इन्होंने जन-जागरण अभियान चलाया और दुकान, प्रतिष्ठान, फैक्ट्री और संवेदक आदि से स्वयं शपथ पत्र लेकर, स्टिकर लगवाकर, हैन्डबिल तथा माईकिंग करवाकर बच्चों के बचपन को बचाने का प्रयास शुरू किया। बच्चों के मन के अन्दर सपना जगाने के लिए लघु फिल्म दिखाकर मोटिवेशन कार्य प्रारंभ करवाया। बालश्रमिक से मुक्ति का प्रारंभ किया इस सदंर्भ में कई सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से भी जन-जागरण का कार्य किया।

श्रम संसाधन विभाग के सभी पक्षों में सकारात्मक, रचनात्मक और गुणात्मक परिवर्तन के लिए भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय की ओर से इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जेनेवा में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक ऑर्गनाइजेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। जेनेवा (स्विटजरलैंड) में तीन दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी किया फिर पेरिस (फ्रांस) में वहाँ के दूतावास में जाकर भारतीय श्रमिकों के सदंर्भ में जानकारी प्राप्त किया खासकर प्रवासी समुद्रपार श्रमिकों का। श्रमिकों के दोहन शोषण और प्रशासनिक परेशानी पर जानकारी प्राप्त किये जिसके आधार पर हमने समुद्रपार जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया।